(ग) राज्य सरकार के उत्तर प्राप्त हो जाने और स्कीम की तकनीकी-आर्थिक व्यवहार्यता सिद्ध हो जाने के बाद इस स्कीम पर योजना आयोग की स्वीकृति प्राप्त करने के लिए आगे कार्यवाही की जाएगी ।

बिहार की बाढ नियंत्रण योजना

3368. **श्री रामावतार शास्त्री :**

क्या सिचाई मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि बिहार सरकार ने केन्द्र सरकार को कोई नई बाढ़ नियंत्रण योजना भेजी है ;

(ख) यदि हां, तो तत्सम्बन्धी ब्यौरा क्या है ; और

(ग) सरकार की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया है ?

सिचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : (क) से (ग). बिहार सरकार ने अक्तूबर, 1981 से अब तक निम्नलिखित चार बाढ़ नियंत्रण स्कीमें गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग को, उनकी जांच और स्वीकृति के लिए प्रस्तुत की हैं :—

क्रम सं०	स्कीमों के नाम	अनुमानित लागत (लाख रुपयों में)	अनुमान की वर्तमान स्थिति
(1)	(2)	(3)	(4)
1	संशोधित हरहा जल निकास स्कीमें	441.42	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा टिप्पणियां फरवरी, 1982 में बिहार सरकार को भेजी गई।
2	फाडो नदी जल निकास स्कीम	124.36	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग में जांच की जा रही है ।
3	जलालपुर सुरक्षा निर्माण-कार्यों के लिए पांचवां अनुमान	106.66	गंगा बाढ़ नियंत्रण आयोग द्वारा 96 लाख की लागत पर स्वीकृति दे दी गई।
4	लोसी बाढ़ तटबंध के चढ़ाव (एफ्लेक्स) बंध के लिए पांचवां अनुमान	752.48	जाँच की अग्रिम अवस्था में ।

Suggestions to raise Paddy Yield

3369. SHRI ANANTHA RAMULU-MALLU: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether some suggestions have been given by the rice experts to demolish the production barrier by greater use of technology and better management practices to raise the yield;

(b) if so, the details in this regard; and

(c) what are the details regarding the total productions of paddy at present, State-wise?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRIES OF AGRICULTURE AND RURAL DEVELOPMENT (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) No such

suggestions have been received by the Ministry of Agriculture in the recent past.

(b) Does not arise.

(c) A statement is enclosed.

Statement

(In lakh tonnes)

States	Production of Paddy– 1980-81
1. Andhra Pradesh	107.00
2. Assam	39-76
3. Bihar	82.14
4. Gujarat	8.35
5. Haryana	18.42
6. Himachal Pradesh	1.45
7. Jammu & Kashmir	8.25
8. Karnataka	33.45
9. Kerala	19.46
10. Madhya Pradesh	60.02
11. Maharashtra	33.69
12. Manipur	4.09
13. Meghalya	2.12
14. Nagaland	1.52
15. Orissa	64.96
16. Punjab	48.34
17. Rajasthan	2.25
18. Tamil Nadu	59.33
19. Tripura	5.85
20. Uttar Pradesh	81.60
21. West Bengal	111.98
22. Union Territories	5.07
Total	799.30

रैनेट की खपत

3370. **श्री कुम्भाराम आर्य :** क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में पनीर बनाने के लिए बछड़ों के अमाशय से प्राप्त रैनेट की खपत कितनी है ;

(ख) एक बछड़े के आमाशय से प्राप्त रैनेट की मात्रा कितनी होती है ;

(ग) क्या देश में रैनेट की मांग बछड़ों से प्राप्त किये गये रैनेट से पूरी हो जाती है अथवा उसका आयात करना पड़ता है ; और

(घ) यदि इसका आयात किया जाता है तो आयात मात्रा कितनी है ?

कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालयों में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन) : (क) से (घ). जानकारी एकत्र करके लोक सभा पटल पर रख दी जाएगी ।

राजस्थान में उठाऊ सिंचाई योजनाएं

3371. **श्री कुम्भा राम आर्य :** क्या सिंचाई मंत्री राजस्थान नहर के पानी को लिफ्ट करने के बारे में 23 नवम्बर, 1981 के अतारांकित प्रश्न संख्या 78, के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि राजस्थान सरकार से कितनी उठाऊ (लिफ्ट) सिंचाई योजनाएं प्राप्त हुई हैं और उन पर क्या कार्यवाही की गई है ?

सिंचाई मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जियाउर्रहमान अंसारी) : राजस्थान सरकार ने सूचित किया है कि पहले परिकल्पित की गई परियोजना के क्षेत्र के बारे में कुछ पुनर्विचार किया गया है और अब कई स्थलों पर लिफ्ट सिंचाई की व्यवस्था करने का भी प्रस्ताव है । यह